+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस)

(January 2024)

(Part III)

TOPICS TO BE COVERED

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- जीएसटी और ईज ऑफ़ डूइंग बिजिनेस

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):

परिचय:

- भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सार्वजनिक खरीद का हिस्सा लगभग 20 से 25 प्रतिशत है। इसका मतलब यह हुआ कि करदाताओं से एकत्र धन का एक बड़ा हिस्सा जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च होता है। ये वस्तुएं और सेवाएं सरकारी कार्यक्रमों को जीवन देती हैं। ऐसी स्थिति में कुशल सार्वजनिक खरीद के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) अपनी शुरुआत के समय से अब तक 60000 करोड़ रुपये से ज्यादा के सरकारी धन की बचत में मददगार रहा है। यह पोर्टल अपनी व्यापक उपलब्धियों की बदौलत विश्व के अग्रणी सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्मों में से एक बन गया है। इसने बेहद कम समय में ही दक्षिण कोरिया के कोनेप्स (KONEPS) और सिंगापुर के जेबिज (GeBIZ) जैसे सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्मों को भी विभिन्न पहलुओं में पीछे छोड़ दिया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के बारे में:

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) की परिकल्पना समावेशी विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और व्यवसाय सुगमता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को अमल में लाने के मकसद से वाणिज्य विभाग के अधीन कंपनी कानून की धारा 8 के तहत विशेष उद्देश्य साधन (SPV) के तौर पर की गई।
- अगस्त 2016 में स्थापित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एक विश्व स्तरीय मजबूत डिजिटल पोर्टल है जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों संगठनों और संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को शुरू से अंत तक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- यह पोर्टल सरकारी खरीदारों को एक ऐसा पेपरलेस कैशलेस एवं कॉन्टैक्टलेस पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है जहाँ वे एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से देश भर के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से सीधे उत्पाद और सेवाएं खरीद सकते हैं। पोर्टल के सामर्थ्य, क्षमताओं और कार्यात्मकताओं का विस्तार करके देश 'में सरकारी खरीद में एक आदर्श बदलाव लाया गया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सार्वजनिक खरीद के लिए डिजिटल समाधान की आवश्यकता:

- सरकारी खरीद अपारदर्शी, समय लेने वाली, बोझिल और भ्रष्टाचार तथा गुटबंदी से ग्रस्त हुआ करती थी। खरीदारों को बेईमान विक्रेताओं से महंगे दामों पर घटिया सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। विक्रेताओं को भी पैनल में शामिल होने और समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी की दया पर दर-दर भटकना पड़ता था।
- आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय से डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल में पूर्ण परिवर्तन की तत्काल जरूरत थी जहाँ किसी भी बाधा के बिना आसानी से व्यापार करने की सुविधा हो और साथ ही उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की खरीद और सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार भी उपलब्ध हो।

जेम की उत्पत्ति:

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस की स्थापना देश के सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र को तकनीकी रूप से उन्नत, मजबूत और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से की गई थी।

- जेम ने खरीद की प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के जरिये, उच्च प्रक्रिया दक्षता, सूचना साझाकरण, बेहतर पारदर्शिता, कम समय में प्रक्रिया पूरी करने और बोलीदाताओं के बीच उच्च स्तर का विश्वास पैदा किया है।
- इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और बचत भी अधिक हुई। जेम में किये गए इन नवाचारों से खरीदारों के लिए समय की बचत और कीमतों में काफी कमी आई और विक्रेताओं का समय पर भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है।
- इसके समावेशी दृष्टिकोण ने एक खुला और विविध सार्वजनिक खरीद बाजार तैयार किया है जो स्टार्टअप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई), महिला उद्यमियों कारीगरों और शिल्पकारों को एक समान अवसर प्रदान करता है।

विकास की दिशा:

- जेम पर खरीद करना संभवत: विश्व स्तर पर किसी भी सरकार द्वारा किए गए सबसे बड़े डिजिटल परिवर्तन अभ्यासों में से एक रहा है।
- कई चुनौतियों के बावजूद, पोर्टल से पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या, कुल खरीद और प्लेटफार्म के माध्यम से किए गए संचयी ऑर्डर मूल्य के मामले में साल-दर-साल महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

- पहले वर्ष में, जेम के जरिये 420 करोड़ रुपये का कुल सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया गया। अगले कुछ वर्षों में. जेम के माध्यम से किए गए लेनदेन वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 38,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 1 लाख करोड़ रुपये हो गए।
- वित्त वर्ष 2022-23 में, जेम ने 88% की वृद्धि दर्ज की, जो 2 लाख करोड़ रुपये के सकल व्यापारिक मूल्य के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर गया।
- चालू वित्त वर्ष 2023-24 में, जेम 3 लाख करोड़ सकल व्यापारिक मूल्य का आंकड़ा पार करने की संभावना है।

जेम पोर्टल द्वारा ईज ऑफ़ डूइंग बिजिनेस को बढ़ावा देना:

- जेम पोर्टल सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को एक ही मंच पर जोड़ता है।
- जेम ने लागत कम करके, दक्षता बढ़ाकर और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर भारत में सार्वजनिक खरीद में क्रांति ला दी है।
- जेम महिला उद्यमियों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, एमएसएमई और स्टार्टअप सहित विविध पृष्ठभूमि के विक्रेताओं को सशक्त बनाता

है, जो कहीं जाये बिना समय पर भुगतान के साथ, कैशलेस और पेपरलेस पारिस्थितिकी तंत्र के तहत वन-स्टॉप-शॉप की पेशकश करता है।

- जेम की पंजीकरण प्रक्रिया आसानी, सुविधा और न्यूनतम डाटा प्रविष्टि को प्राथमिकता देती है।
- जेम ने 'विवाद से विश्वास-II' (संविदात्मक विवाद) की शुरुआत की है जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए एक बेहतरीन सुविधा है।
- **जेम सहायः** एमएसएमई और स्टार्टअप के सामने आने वाली ऋण हासिल करने की चुनौतियों के समाधान के लिए जेम सहाय शुरू किया गया है।

भविष्य के लिए रोडमैप:

- जैसे-जैसे यह प्लेटफॉर्म विकसित हो रहा है और महत्वपूर्ण सुधार ला रहा है, यह विकास के अगले पड़ाव को शुरुआत कर रहा है, इससे राज्यों में खरीद की प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है।
- जेम का रणनीतिक फोकस सभी स्तरों पर सरकारी खरीदारों को अपने मजबूत ई-खरीद बुनियादी ढांचे में एकीकृत करके अपनी पहुंच का विस्तार करने पर है। ज्यादा से ज्यादा राज्य अब जेम के माध्यम से खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- जेम का खरीददार विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र और उसका कामकाज थोड़े समय में ही एमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट के मिलेजुले दायरे से भी दोगुना बड़ा हो गया है।
- उसने एक ऐसी अवसंरचना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है जो डाटा एकत्र करने के साथ ही सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं की शुरुआत से अंत तक की गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है।
- यह प्लेटफॉर्म अपने कामकाज में सुधार के साथ ही नए जमाने की प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उपयोगकर्ता के अनुभव में सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि तथा सार्वजनिक खरीद की प्रक्रिया में ज्यादा समावेशन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

जीएसटी और ईज ऑफ़ डूइंग बिजिनेस:

परिचय:

- 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आजादी के बाद वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अप्रत्यक्ष करों में लागू किया सबसे बड़ा सुधार है। जीएसटी लागू होने के साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्द्धित कर (वैट), क्रय कर, प्रवेश कर, केंद्रीय विक्री कर, स्वायत्त निकाय कर, विलासिता कर, चुंगी इत्यादि अनेक केंद्रीय और राज्य कर समाप्त हो गए।

- इससे आर्थिक अवरोध कम हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित अर्थव्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुल गया है।
- नतीजा यह हुआ कि विगत छह वर्षों में जीएसटी का कर आधार 67.8 लाख से बढ़कर करीब 1.4 करोड़ हो गया और अप्रैल, 2023 में 1,87,035 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व एकत्र हुआ जो अब तक का सर्वाधिक है।

- नवम्बर, 2023 में मासिक राजस्व संग्रह, 1,67,929 करोड़ रुपये रहा जिसमें ईयर ऑन ईयर अर्थात् वार्षिक वृद्धि के आधार पर सर्वाधिक 15 प्रतिशत वृद्धि हुई।

जीएसटी व्यवस्था का व्यापार सुगमता पर प्रभाव:

- करों के मूल्यों पर पड़ने वाले तीव्र प्रभाव को कम करके जीएसटी ने समूचे व्यापार परिवेश में सुधार लाकर कारोबार को सरल-सुगम बनाने के उद्देश्य से बाज़ारों में स्पर्धा की भावना विकसित की है।
- जीएसटी अनुपालन को कम करने, राज्यों में माल के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने कानूनों प्रक्रियाओं, कर की दरों, सामान्य परिभाषाओं और इंटरफेस को माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के माध्यम सुसंगत बनाने पर केंद्रित है जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड की कार्य-दक्षता बढ़ती है और आपसी तालमेल बेहतर होता है।
- कंसल्टिंग फर्म डेलॉइट के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार जीएसटी के बारे में करीब 70 प्रतिशत बिजनेस लीडर्स ने बढ़ती हुई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

- इसमें सभी आकार के कारोबारों पर सकारात्मक प्रभाव का संकेत है जिनमें सूक्ष्म, लघु और मझौले (एमएसएमई) उद्योग जीएसटी का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- लगभग 88 प्रतिशत एमएसएमई प्रतिनिधियों ने वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम होने का तथ्य स्वीकार किया है और इसका श्रेय जीएसटी व्यवस्था की अधिक समानता पर आधारित प्रणाली को दिया गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत के बेहतर प्रदर्शन में जीएसटी सुधार का महत्व:

- विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में देशों का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंडों में देश की कराधान प्रणाली अहम है।
- आर्थिक और कर सुधारों के बल पर ही भारत सूचकांक सूची में लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है: इसका स्थान 2014 में 142वां था जबकि देश 2018 में 77वें स्थान पर आ गया तथा 2019 में 63वां स्थान प्राप्त कर लिया।

जीएसटी में कंप्यूटरीकरण महत्व:

- जीएसटी की इतनी जबरदस्त कामयाबी का श्रेय स्वचालन (कंप्यूटरीकरण) और मानकीकरण को दिया जा सकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- किसी भी व्यापार-चक्र के लिए पंजीकरण आवेदन से लेकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड के लिए आवेदन करने, नोटिसों का जवाब देने, अपील दायर करने जैसे सभी कार्य ऑनलाइन हो जाने के कारण कर अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क रखने का झंझट पूरी तरह समाप्त हो गया है।
- 'कारोबार करने की सुगमता' के यहीं आवश्यक घटक है।

जीएसटी सुधार एवं व्यापार सुगमता का आगे का रास्ता:

- उद्योग और घरेलू व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की व्यापक सुधार कार्य-योजना, 2020 में भी देशभर में व्यापार को सुगमता में महत्वपूर्ण सुधार का संकेत दिया गया है।
- नई कर प्रणाली जीएसटी अपनाने में आए शुरुआती झटकों के बावजूद इसे कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में और सप्लाई चेन की कुशलता सुधारने की दृष्टि से अहम बदलाव माना गया है। करदाताओं के लिए नियम-परिपालन का बोझ कम करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- अप्रत्यक्ष कर सुधारों के पीछे की असल भावना, उसके क्रियान्वयन तथा करदाताओं पर उसके अपेक्षित प्रभाव में कोई कसर या कमी नहीं है। जीएसटी तंत्र की अपनी कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन इसके फायदे कहीं ज्यादा है और नुकसान काफी कम।
- जीएसटी परिषद के सही प्रयासों के फलस्वरूप यह प्रणाली अधिक समानता पर आधारित और कुशल बन सकी है जिससे यह सुधारात्मक उपाय इतनी बड़ी सफलता पा सका है।